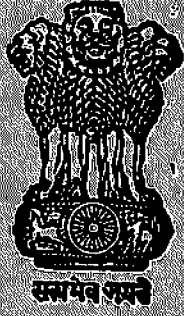


188-B
7-9-2002

पुस्तकालय



असंशोधित

30 MAR 2001

बिहार विधान-सभा वादवृत्ता

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग-२-कार्यवाही-प्रश्नोत्तर रहित)

वि. स. मा. नं. (एच. ए.) 99/2-10,000-4-9-1996-वटवट, ।

ई:50:अंगी:दि 30.3.2001

श्री प्रहलाद दादव, राज विहार की ध्यानाकर्षण-सूचना पर सरकार
उन एवं पर्यावरण विभागों को ओर से वक्तव्य ।

डा० रामचन्द्र पूर्वी मंत्री: महोदय, संबंधित मंत्री विधान-परिषद् में है। इसलिए इसका जवाब कल
देगे ।

अध्यक्ष: अभी माननीय मंत्री विधान-परिषद् में है। आप बैठिए, आज ही इसका
जवाब होगा ।

श्री आनन्दी प्रसाद दादव, राज विहार केसरी एवं अन्य चार सभासदों की
ध्यानाकर्षण-सूचना पर सरकार जल संसाधन विभागों को ओर से वक्तव्य ।

श्री इन्द्रदेव प्रसाद राज्य मंत्री: महोदय, उत्तर विहार की बाढ़ की समस्या के निदान हेतु राज्य-
सरकार शतवत् तत्पर है। समस्या के अल्प-कालीन तथा मध्यम कालीन उपाय के
तहत उत्तर विहार की नदियों पर कुल लगभग 2952 किमी० तटबंधों का निर्माण
किया गया है, जिससे काफी हद तक बाढ़ को नियंत्रित करने में काम किया जा
सका है। इन्हें और अधिक प्रभावी बनाने हेतु लालबकेवा, वागमती, काला तथा
खण्डो नदियों पर विहार क्षेत्र में निर्मित तटबंधों का सुदृढीकरण तथा इनके
नेपाल क्षेत्र में निस्तार कर ऊँची भूमि से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। इनमें से
लालबकेवा तटबंध योजना पर कार्य प्रगति पर है।

बाढ़ की समस्या के दीर्घकालीन उपाय के तहत प्रमुख नदियों पर जलाशयों
का निर्माण विरोधों की राह में आवश्यक माना गया है। किन्तु, उपर्युक्त बांध-
स्थलों के नेपाल क्षेत्र में अपस्थित रहने के कारण विस्तृत योजना प्रीतियेदन तैयार
करने हेतु आवश्यक सर्वेक्षण तथा अनुसंधान कार्य प्रारंभ करने के लिए भी नेपाल
सरकार की सहमति आवश्यक है। इस प्रकार पहचान किए गए इस स्थल सप्तकोशी
नदी पर बराहक्षेत्र, काला नदी पर तेतीरथा तथा वागमती पर नूनकोर में अपस्थित
है। इन परियोजनाओं के संबंध में नेपाल सरकार से अपेक्षित सहयोग प्राप्त करने

हेतु राज्य सरकार विभिन्न स्तरों पर केन्द्र से सतत अनुरोध करती रही है किन्तु इस विषय पर उल्लेखनीय प्रगति वर्ष 1991 में नेपाल के प्रधानमंत्री को भारत यात्रा के दौरान हुई, जब सप्तकोशी बाँध परियोजना का विस्तृत योजना प्रतिकेदन तैयार करने हेतु भारत-नेपाल संयुक्त विशेषज्ञ दल गठित किया गया। सप्तकोशी बाँध डैम हेतु संयुक्त विशेषज्ञ दल के गठन से अतक इसकी तीन बैठकें हो चुकी है। जिसमें से पहली द्वितीय बैठक 21-23 मार्च, 2001 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। इस बैठक में अगले दस वर्षों की अवधि के भीतर सप्त कोशी बाँध डैम द्वारा क्षेत्रों का विस्तृत योजना प्रतिकेदन तैयार करने एवं सप्तकोशी बाँध डैम परियोजना कार्यालय, काठमाण्डू में संयुक्त कार्यालय तथा दो प्रारंभिक कार्यालय उपयुक्त स्थान पर अधीनस्थ खोलने का निर्णय लिया गया। काला तथा वागमती नदियों पर प्रस्तावित जलाशय से संबंधित विषय भी इसी संयुक्त दल के विचाराधीन है।

राज्य सरकार के सतत प्रयत्न के फलस्वरूप भारत और नेपाल के बीच जल संसाधन संधि स्तर पर एक संयुक्त गठित की गई है। इस संधि में विहार-सरकार के जल संसाधन आयोग एवं संधि भी सदस्य हैं। इस संधि की पहली बैठक दिनांक 1-3 अक्टूबर, 2000 को काठमाण्डू में सम्पन्न हुई। इस बैठक में सप्तकोशी बाँध डैम का सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य प्रारम्भ करने हेतु कार्यालय खोलने आदि के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये।

अन्तर्राष्ट्रीय विवाद होने के कारण राज्य सरकार को ओर से इस संबंध में अत्यंत सीमित भूमिका होने के बावजूद राज्य सरकार सतत केन्द्र सरकार के संपर्क में है तथा इस योजना को पूर्ण स्वरूप देने हेतु प्रयत्नशील है।